भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1452
बुधवार, 12 मार्च, 2025 (21 फाल्गुन, 1946 (शक)) को उत्तरार्थ

प्राथमिक सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण

1452# श्री महेंद्र भट्टः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कुल कितनी प्राथमिक सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है;

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इसके लिए प्रशिक्षित कम्प्यूटर कार्मिकों की नियुक्ति हेतु कोई नीति बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख) भारत सरकार ने कुल ₹2,516 करोड़ के वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को अनुमोदित किया है जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को एक ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के साथ लिंक करना है । इस परियोजना के अधीन 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से कुल 67,930 पैक्स स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से दिनांक 27.01.2025 की स्थिति के अनुसार 50,455 पैक्स को ERP सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड किया गया है । ऑनबोर्ड किए गए पैक्स की राज्य-वार सूची **अनुलग्नक** में संलग्न है ।

(ग) पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सॉफ्टवेयर के उपयोग पर प्रशिक्षण की मूल जिम्मेदारी इस परियोजना के लिए नाबार्ड द्वारा नियुक्त नेशनल लेवल पैक्स सॉफ्टवेयर वेंडल (NLPSV) की होगी । राष्ट्रीय और राज्य-स्तर पर प्रशिक्षकों की सुगम उपलब्धि के लिए संबंधित राज्यों और राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा नियुक्त राज्य स्तरीय सिस्टम इंटीग्रेटर्स (SIs) को NLPSV द्वारा आवश्यक इनपुट्स प्रदान किए जाएंगे । सहकारी क्षेत्र के सभी प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षक लिए जाएंगे । सॉफ्टवेयर में माइग्रेशन के बाद, PACS के कर्मचारियों को सॉफ्टवेयर और उस पर काम करने के तरीके के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा । सॉफ्टवेयर पर निर्बाध कार्यकरण की सुविधा के लिए नाबार्ड द्वारा संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें अब तक 17 प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से पैक्स के 1,42,746 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है ।

*****

अनुलग्नक

क्रम सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	कंप्यूटरीकरण के लिए चयनित PACS	ERP पर ऑनबोर्ड किए गए
1.	महाराष्ट्र	12,000	10,979
2.	राजस्थान	6,781	4,206
3.	गुजरात	5,754	5,249
4.	उत्तर प्रदेश	5,686	2,978
5.	कर्नाटक	5,491	2,077
6.	मध्य प्रदेश	4,536	4,516
7.	तमिलनाडु	4,532	4,529
8.	बिहार	4,495	4,440
9.	पश्चिम बंगाल	4,167	1,103
10.	पंजाब	3,482	1,720
11.	आंध्र प्रदेश	2,037	1,734
12.	छत्तीसगढ़	2,028	2,010
13.	हिमाचल प्रदेश	1,789	836
14.	झारखंड	1,500	1,467
15.	हरियाणा	710	617
16.	उत्तराखंड	670	185
17.	असम	583	580
18.	जम्मू और कश्मीर	537	531
19.	त्रिपुरा	268	245
20.	मणिपुर	232	45
21.	नागालैंड	231	33
22.	मेघालय	112	103
23.	सिक्किम	107	107
24.	गोवा	58	35
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	46	46
26.	पुड्डुचेरी	45	37
27.	मिजोरम	25	25
28.	अरुणाचल प्रदेश	14	11
29.	लद्दाख	10	9
30.	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4	2
कुल		**67,930**	**50,455**